इस पूछ-ताछ में कोई उपयोगी सूचना नहीं मिली । अतः 12-12-1977 को उसे व्यक्तिगत मुचलके पर छोड़ दिया गया ।

Production of Urea Based Fertilizers

*11. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether there is a shortfall in the production of urea based fertilizers;

(b) if so, the reasons thereof; and

(c) the steps taken to meet the shortage?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI JANESHWAR MISHRA): (a) Production of Urea fertilizer during 1977-78 is expected to be 32 lakh tonnes as against a target of 34 lakh tonnes.

(b) Th e shortfall in production of Urea is due to a variety of factors like mechanical breakdowns, power cuts, instability in power supply and labour problems.

(c) Adequate imports have been planned to meet the gap between the demand and the indigenous availability.

बम्बई के निकट समुद्र तल में विकास के लिए विश्व बैंक से ऋण

*12. **श्री मनोहर लाल** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने बम्बई के निकट समुद्र तल में तेल की खोज और विकास कार्य के लिए ऋण मंजूर किया

(ख) यदि हां, तो ऋण की राशि कितनी है, इसकी ब्याज की दर और अन्य शर्तें क्या हैं ; और

(ग) इस ऋण का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जायेगा और उससे कितना लाभ मिलेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां । अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक ने बम्बई हाई विकास के कार्यक्रम के चरण—III के कार्यान्वयन हेतु एक ऋण देना मंजूर किया है ।

(ख) ऋण की राशि 150 मिलियन अमेरीकी डालर 134 करोड़ रुपये से कुछ ऊपर है । इस ऋण में से ली गई धन राशि पर वार्षिक 8.2 प्रतिशत की दर से ब्याज होगा और न ली गई धन राशि पर वार्षिक एक प्रतिशत का तीन-चौथाई वचनबद्ध प्रभार वसूल किया जायेगा; और ब्याज तथा वचनबद्ध प्रभार प्रतिवर्ष अर्ध-वार्षिक देय हैं । मूलधन 1 जनवरी, 1981 से आरम्भ करके 1 जनवरी 1997 तक 4,410,000 अमरीकी डालर की समान अर्ध वार्षिक किस्तों में लौटाया जाना है तथा 4,470,000 अमेरीकी डालर की अन्तिम किस्त 1 जुलाई, 1997 को दी जायेगी ।

(ग) यह ऋण बम्बई हाई परियोजना के चरण—III के विकास कार्य के लिए आंशिक रूप से धन की व्यवस्था हेतु दिया गया है । इस समय जिस रूप में इस ऋण परिकल्पना की गई है, उसे निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए प्रयोग किया जायेगा :—

(i) अन्तः सागरीय पाइपलाइनों की प्रतिस्थापना करना;

(ii) दो कुआं प्लेटफार्मों और दो तेल साफ करने वाले प्लेटफार्मों के

लिए उपकरण और उनका निर्माण करना;

(iii) गैस विखंडन संयंत्र के लिए उपकरण और उनका निर्माण करना।

बम्बई हाई के विकास के लिए चरण—3 के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने से, जिसमें उत्तर बसीन क्षेत्र का आंशिक विकास कार्यक्रम भी सम्मिलित है, बम्बई हाई क्षेत्र से वार्षिक लगभग 6 मिलियन मी० टन तथा उत्तर बसीन क्षेत्र से वार्षिक एक मिलियन मी० टन तेल की उत्पादन क्षमता को सुनिश्चित करने में सहायता होगी।

Reservation of Assembly/Parliamentary Constituencies for Scheduled Castes

*13. SHRI RAMANAND TIWARY: Will the Minister of LAW, JUSTICE, AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) the yardstick for reserving Assembly/Parliamentary constituencies for Scheduled Castes and the time for which these are reserved;

(b) the number and details of Parliamentary constituencies reserved as such, State-wise, and the period for which they are reserved; and

(c) the legal or administrative reasons for keeping the constituencies reserved for more than 10 or 15 years and the steps contemplated to be taken to declare them as general seats for future?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) Reservation of Assembly /Parliamentary constituences for Scheduled Castes is made under the provisions of articles 330 and 322 of the Constitution, read with the relevant provisions of the law made in this behalf under articles 82 and 170(3) if the Constitution. The period for which the constituencies are reserved is thirty years from the commencement of the Constitution under article 334 of the Constitution.

(b) A statement showing the particulars of parliamentary constituencies, state-wise, that are reserved for Scheduled Castes under the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976 is enclosed. The reservation of seats in respect of these constituencies came into effect from the date of dissolution of the last House of the People. The seats would normally continue to be reserved till a fresh delimitation of constituencies is made. However, under article 334 of the Constitution as it stands at present, the reservation will cease on the expiration of a period of 30 years from the commencement of the Constitution.

(c) The Constitution provides for the reservation of seats for the Scheduled Castes in the House of the People in order to guarantee a minimum number of seats to the members of such Castes in that House. There is no proposal under consideration to declare the seats reserved for Scheduled Castes in the House of the People as general seats.

Statement

Serial Number and Name of State/Union territory	Total seats	No. of seats reserved for SCs	Serial Number and Name of constituency reserved
1	2	3	4
STATES			
1. Andhra Pradesh	42	6	9-Amalapuram, 19-Nellore, 20-Tirupathi, 28-Nagarkurnool, 32-Siddipet and 36-Peddapalli.